boundary wall in the middle of 45 feet wide road around their colony on Malviya Nagar Road in front of Panchsheel Club in violation of the provisions of Delhi Master Plan and directions of D.D.A.;

(b) if so, why this boundary wall was allowed to be constructed;

(c) whether any responsibility on the concerned officers and penalty have been fixed for this wasteful expenditure; and

(d) by what time the 45 feet road will be restored for public use after removing this unauthorised wall?

THE MINISTER OF WORKS AND HOUSING AND SUPPLY AND REHABILITATION (SHRI SIKANDAR BAKHT): (a) Yes, Sir.

(b) The Central Provident Fund Commission have constructed the boundary wall unauthorisedly without permission.

(c) It is for the Central Provident Fund Commission to take necessary action in the matter against officers etc.

(d) The road is to be developed jointly by the Central Provident Fund Commission and Sarvapriya Vihar Co-operative House Building Society. The 45 feet road can be developed only by dismantling the boundary wall. Necessary action for dismantling the same has been initiated by the Delhi Development Authority.

केन्द्रीय विश्वविद्यालय के कर्मचारियों को ऋण सुविधाएं

845. **श्री हरगोविन्द वर्मा :** क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के कर्मचारियों को ऋण सुविधायें देने के बारे में सरकार द्वारा सैद्धांतिक रूप में लिये गये निर्णय के बाद, इस वर्ष के दौरान कुछ व्यक्तियों को ऋण मंजूर करने के लिए सरकार से कोई प्रावधान किया है ;

(ख) यदि हां, तो उसकी राशि कितनी है और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) उक्त ऋण उन्हें कब तक दिया जायेगा ;

(घ) क्या कर्मचारियों को आवंटित प्लाटों पर मकानों का निर्माण करने के लिए दी गई अवधि का विस्तार करने के लिए शिक्षा मंत्रालय निर्माण और आवास मंत्रालय से अनुरोध करेगा ; और

(ङ) यदि नहीं, तो इस स्थिति से निपटने के लिए शिक्षा मंत्रालय का केन्द्रीय विश्वविद्यालय के कर्मचारियों की किस प्रकार सहायता करने का विचार है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) स (ग), केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के कर्मचारियों को गृह निर्माण के लिए ऋण प्रदान करने के संबंध में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का प्रस्ताव, जिसे सिद्धान्त रूप से स्वीकार कर लिया गया है, 1979-80 के दौरान निधियों की उपलब्धता के आधार पर कार्यान्वित किए जाने की आशा है ।

(घ) केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के कर्मचारियों से इस प्रकार का कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है ।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता ।

अन्त्योदय कार्यक्रम की क्रियान्वित के लिए सहायता

846. **श्री रूप नाथ सिंह यादव :** क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों में सरकार ने राजस्थान में अन्त्योदय कार्यक्रम की क्रियान्विति और बेरोजगारी और गरीबी को दूर करने के लिए कितनी सहायता की व्यवस्था की है ;

(ख) क्या सरकार ने उक्त कार्यक्रमों की क्रियान्विति के लिए अन्य राज्य सरकारों को कोई मार्गदर्शी सिद्धान्त भेजे हैं, और

(ग) यदि हां, तो सरकार ने उत्तर प्रदेश के कितने गांवों में उक्त कार्यक्रम आरम्भ किए हैं ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : (क) केन्द्रीय सरकार का राजस्थान को केन्द्रीय क्षेत्र/केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना के अन्तर्गत

विशेषरूप से अन्त्योदय कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए कोई वित्तीय आवंटन करने का प्रस्ताव नहीं है। तथापि, लघु कृषक विकास एजेंसी, सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम, कमाण्ड क्षेत्र विकास तथा काम के बदले अनाज कार्यक्रमों जिन्हें 1976-77 और 1977-78 के अंतिम दो वर्षों के दौरान राजस्थान में बेरोजगारी तथा गरीबी को दूर करने के लिए रखा गया है, जैसी योजनाओं के अन्तर्गत 21.49 करोड़ तक निधियां सुलभ की गई।

(ख) व (ग) अन्त्योदय कार्यक्रम के बारे में किसी भी राज्य को कोई मार्गदर्शक सिद्धान्त नहीं भेजे गए हैं। तथापि, उत्तर प्रदेश सरकार ने इस कार्यक्रम को अपने सभी 876 विकास खण्डो में शुरू किया है जिससे अब तक 23,293 परिवारों को लाभ पहुंचा है।

Expenditure on Relief and Rehabilitation in flood affected West Bengal

848. PROF. SAMAR GUHA: Will the Minister of AGRICULTURE AND IRRIGATION be pleased to state:

(a) the aids given to West Bengal, in cost and kind, by the Central Government for relief and rehabilitation of the flood victims of the State;

(b) the amount so far spent by the State Government and the schedule for their expenditure for the above purposes;

(c) whether the Government received report about the expenditure from the State Government; and if so, facts thereabout;

(d) whether complaints about irregular expenditure and some corrupt practices have been voiced in West Bengal; if so, facts thereabout: and

(e) whether the Central Team have made any investigation about the nature of the expenditure of the Centra aids; if so, facts thereabout?

THE MINISTER OF AGRICULTURE AND IRRIGATION (SHRI SURJIT SINGH BARNALA): (a) The Union Government have allocated to the Government of West Bengal, the following assistance for relief and rehabilitation of the flood victims:

	(Rs. in crores)
1. Advance Plan assistance for relief of natural calamity .	88·93
2. 1,15,500 tonnes of foodgrains and pulses for gratuitous relief	15·89
3. 1,50.000 M.Ts of foodgrains under Food for Work Programme	18·75
4. Short term loan for agricultural inputs	25·00
5. Value of medicines etc. (supplied on credit payment basis)	0·37
Total . . .	148·94

(b) and (c). According to the information furnished to the Central Team which visited the State recently, the State Government have incurred an expenditure of Rs. 61.80 crores on various items upto 31-1-1979.

(d) No specific complaints have been received in this behalf.

(e) The Central Team which visited the State from the 15th to the 17th February, 1979 reviewed the progress of expenditure of the Central assistance and held discussions with the State Officials. The team has asked for certain particulars from the State Government. It's report can be finalised only on receipt of those particulars from the State Government.

गौतमपुरी, शाहदरा में सड़कों की मरम्मत

849. श्री रामदेव सिंह :

श्री अचल सिंह ठाकुर :

क्या निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि यमुना-पार बस्ती गौतमपुरी में जो सड़कें तथा गलियां हाल ही की भारी